

संपादकीय

जब अमेरिका ने सबको डरा दिया

अमेरिका में चुनावी साल (राष्ट्रपति चुनाव) के किसी भी अन्य महीने की अगले मार्च, 2020 की शुरुआत हुई थी। यादातर अमेरिकी इस महीने की अपनी दो पसंदीदा गतिविधियों में मग्न थे। पहली, 3 मार्च के 'सुप एयूजड' (इस मंगलवार को यहां के यादातर राय अपनी प्राइमरी का चुनाव खड़ा करते हैं) पर नजर बनाए रखना और दूसरी, कॉलेज बास्केट बॉल के फाइनल जूदा सीजन के आखिरी मैचों का लुक्क उठाना। भले ही इटली और स्पेन ने कोविड-19 के कारण हो रही मौतें रोजाना खबरों में आ रही थीं, लेकिन यहां इस महामारी को आम जननामनस कोई खतरा नहीं मान रहा था। मगर जल्द ही हालात बदल गए। कोरोना वायरस के तेज़ प्रसार को देखते हुए नेतकालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 मार्च को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। फिर भी, इस मुल्क की क्या दशा हुई, इसे देश-दुनिया ने देखा। अगले 12 महीनों में अमेरिका लगभग तबाह हो गया। कोविड-19 ने 5.5 लाख से अधिक अमेरिकियों का जीवन छीन लिया और इसकी कुल आवादी का दसवां हिस्सा अब तक संक्रमित हो चुका है। इसने काफी आर्थिक चोट भी पहुंचाई। जब कोरोना चरम पर था, तब कुछ ही हफ्तों में नाखों अमेरिकियों ने अपनी नौकरी गंवाई और बेरोजगारी दर लगभग 15 फीसदी पर पहुंच गई। 'प्यू रिसर्च सेंटर' के मुताबिक, एक तिहाई व्यस्क अमेरिकियों को पिछले साल बिल भुगतान में दिक्कतें आई। कोरोना की वजह से अमेरिका का यह पतन पूरी दुनिया को प्रभावित कर गया, क्योंकि यह एष्ट्रॉवैशिक अर्थव्यवस्था का अगुवा है। उत्तरी अमेरिका में तो उत्पादों के आयात-नियात का कारोबार 2019 की तुलना में 20 फीसदी से अधिक घट गया। अब कोविड-19 की पहली बरसी के बाद समाज वैज्ञानिक, डॉक्टर और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह पता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर दुनिया भर में सबसे अधिक खर्च खरने वाला अमेरिका आखिर कोरोना से इस कदर कैसे बर्बाद हो गया, जबकि इससे कम विकसित देश महामारी से बहुत यादा प्रभावित नहीं हुए? और क्या इसका इस तथ्य से बाकई कोई संबंध है कि विकासशील देशों में नोएं साफ-सफाई को लेकर कुछ कम संजीवा रहते हैं, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ उन्होंने प्रतिरोधक क्षमता तैयार कर ली थी? इन नवालों के ठीक-ठीक जवाब तो हमें शायद वर्षों बाद मिलें, लेकिन जो हम आज जानते हैं, वह यही है कि उचतम स्तर पर नेतृत्व की विफलता और नार्वर्जनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की दशकों से उपेक्षा अमेरिका पर मारी पड़ गई। यादा संभवाना तो इसी बात की है कि अगर 'ओवल ऑफिस' (राष्ट्रपति कार्यालय) में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई दूसरा शख्स बोलता, तो संभवतः महामारी का यूं प्रसार न होता। जब संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ था, तब ट्रंप दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारियों में व्यस्त थे, जबकि 2020 की शुरुआत में ही जैसे-तैसे वह महाभियोग से बच पाए थे। वह इस अर्थव्यवस्था के आधार पर जनादेश हासिल करना चाहते थे, जिसे नाल 2018 में बड़े पैमाने पर की गई कर कटौती के रूप में वह 'स्ट्रैंगर्ड' दुके थे। कर छूट से कुछ हृद तक अमेरिकियों को जरूर लाभ मिला था, लेकिन इसका फायदा असमान रूप से अमीरों ने उठाया। यहां तक कि अश्विमी युगों में कोरोना के कहर को देखने के बावजूद ट्रंप ने इसके कमतर

दिल्ली जैसे शहरों में शोर
की मात्र कहीं यादा है,
जहां ध्वनि प्रदूषण की
रोकथाम करने वाले कई
कानून पिछले एक दशक
से यादा समय से अस्तित्व
में हैं। आवासीय इलाकों में
ध्वनि की मात्र अधिकतम
55 डेसिबल, व्यापारिक
इलाकों में 65 डेसिबल
और औद्योगिक क्षेत्रों में
75 डेसिबल होनी चाहिए,
प्रैकिन हर जगह यह करीब
25 डेसिबल अधिक है।
इस कारण कभी-कभी
नौबत रोड रेज जैसी
गटनाओं की भी आ जाती
है। बहहाल शांति का
महत्व जानते हुए भी यह
लापरवाही घातक है कि
इम शोर को अपनी राष्ट्रीय
पहचान बनाने की छूट दे
रहे हैं। ध्यान रखना होगा
के सिर्फ कानून ये हालात
नहीं बदल सकते। लोगों
की मानसिकता बदले बगैर
शोर जैसी समस्या से
नेजात पाना नामुमकिन ही

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर उनके घर की तरफ नजदीकी मस्जिद से सुबह होने वाली अजान से नींद टूटने की समस्या का उल्लेख किया तो इस पर एक सकारात्मक जवाब मस्जिद की ओर से आया। प्रयागराज के कानपुर रोड स्थित लाल मस्जिद के मुतवल्ली रहमान ने कुलपति की पेशानी का समाधान करते हुए उनकी ओर के लाउडस्पीकर की दिशा बदल दी और आवाज भी 50 फीट सड़ घटा दी। आम तौर पर ऐसे मामलों में अक्सर तीखी धार्मिक प्रतिक्रिया होती रही है और शेर को समस्या न मानकर उन मार्गों को मजहबी रंग दिया जाता रहा है। यह अछूत है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह मामला अजान तक नहीं रुकना चाहिए। हर किस्म के धार्मिक जुलूसों के मामलों में भी यह होना चाहिए। शेर या कहें कि ध्वनि प्रदूषण हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है, इस पर हमारी नजर इसलिए नहीं जाती है, क्योंकि हममें से यादातर भारतीय इसके आदी हो चुके हैं। उन्हें यह स्वाभाविक लगता है। इसमें हर किस्म का शेर शामिल है। जैसे-सार्वजनिक जगहों पर तेज प्लूजिक बजाना, सड़कों पर बाहनों के हाँन बेवजह बजाना, अस्पतालों से लेकर लाइब्रेरी तक में लोगों को तेज आवाज में बताएं करते देखना और कुछ न हो सके तो लाउडस्पीकर लगाकर तेज आवाज में धार्मिक आह्वान करना।

कायदे-कानून बनाए गए हैं, पर उमारी सरकारें नियम-कानून बनाकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री बनाने लेती हैं। इसलिए आजादी के बाद इस स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पाया है। वर्ष 2012 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलय के नेटवर्कवधान में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचना नारी की गई थी, जिसके तहत 25 बांकड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण की नेगरानी के लिए एक नेटवर्क बनाने की बात कही गई थी। इस नेटवर्क में हर शहर में 10-10 नेगरानी केंद्र बनाए गए, जो यह दखते हैं कि कहाँ कितना प्रदूषण है। फिर यदि अभी तक हमारे पास जगधानी दली को छोड़कर किसी भी शहर के बारे में अधिकृत आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि देश में शोर को मापने की कोई व्यवस्था ठीक नहीं से काम कर ही नहीं रही है।

दिल्ली जैसे शहरों में शोर की मात्र कहीं यादा है, जहाँ ध्वनि प्रदूषण की नियोकथाम करने वाले कई कानून पछले एक दशक से यादा समय से अस्तित्व में हैं। आवासीय इलाकों में ध्वनि की मात्र अधिकतम 55 डेसिबल, व्यापारिक इलाकों में 65 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्रों में 75 डेसिबल होनी चाहिए, लेकिन यह जगह यह करीब 25 डेसिबल अधिक है। इस कारण कभी-कभी नौबत रेड रेज जैसी घटनाओं की भी आ जाती है। बहरहाल शांति का नहत्या जानते हुए भी यह लापरवाही यात्रक है कि हम शोर को अपनी अप्रीय पहचान बनाने की छूट दे रहे हैं। ध्वनि रखना होगा कि सिर्फ कानून ये हालात नहीं बदल सकते। तोगों की मानसिकता बदले बगेर गोर जैसी समस्या से निजात पाना मुमकिन ही है।

राष्ट्रीय समस्या बनता जा रहा सार्वजनिक स्थलों पर शेर, मानसिक सेहत के लिए भी खतरनाक

दिल्ली जैसे शहरों में शेर की मात्र कहीं यादा है,
जहां ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करने वाले कई कानून पिछले एक दशक से यादा समय से अस्तित्व में हैं। आवासीय इलाकों में ध्वनि की मात्र अधिकतम 55 डेसिबल, व्यापारिक इलाकों में 65 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्रों में 75 डेसिबल होनी चाहिए, लेकिन हर जगह यह करीब 25 डेसिबल अधिक है। इस कारण कभी-कभी नौबत रोड रेज जैसी घटनाओं की भी आ जाती है। बहरहाल शांति का महत्व जानते हुए भी यह लापरवाही घातक है कि हम शेर को अपनी राष्ट्रीय पहचान बनने की छूट दे रहे हैं। ध्यान रखना होगा कि सिफ्फ कानून ये हालात नहीं बदल सकते। लोगों की मानसिकता बदले बगैर शेर जैसी समस्या से निजात पाना नामुमकिन ही है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर उनके घर की तरफ नजदीकी मस्जिद से सुबह होने वाली अजान से नींद टूटने की समस्या का उल्लेख किया तो इसने पर एक सकारात्मक जवाब मस्जिद की ओर से आया। प्रयागराज के कानपुर रोड स्थित लाल मस्जिद के मुतवली रहमान ने कुलपति की परेशानी का समाधान करते हुए उनकी ओर के लाउडस्पीकर की दिशा बदल दी और आवाज भी 50 फीसद घटा दी। आम तौर पर ऐसे मामलों में अक्सर तीव्री धार्मिक प्रतिक्रिया होती रही है और शेर को समस्या न मानकर उन मांगों को मजबूती रंग दिया जाता रहा है। यह अच्छा है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह मामला अजान तक नहीं रुकना चाहिए। हर किस्म के धार्मिक जुलूसों के मामलों में भी यह होना चाहिए। शेर या किंवि कि ध्वनि प्रदूषण हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है, इस पर हमारी नजर इसलिए नहीं जाती है, क्योंकि हममें से यादातर भारतीय इसके आदी हो चुके हैं। उन्हें यह स्वाभाविक लगता है। इसमें हर किस्म का शेर शामिल है। जैसे-सार्वजनिक जगहों पर जेजू म्यूजिक बजाना, सड़कों पर बाहनों के हाँने बेवजह बजाना, अस्पतालों से लेकर लाइब्रेरी तक में लोगों को तेज आवाज में बातें करते देखना और कुछ न हो सके तो लाउडस्पीकर लगाकर तेज आवाज में धार्मिक आह्वान करना।

करीब चार साल पहले 2017 में बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनूनियां ने भी कुछ ऐसी ही बातें अपने टिवटर अकाउंट पर लिखी थीं, लेकिन तब देखते ही देखते उन्हें तमाम धर्मगुरुओं ने उनके विवादित बयानों के लिए घेर लिया था। सोनू

स्तर औसतन 90 डेसिबल से यादा है। मुंबई को तो एक दफा दुनिया का तीसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बताया गया था और इसके ठीक बाद दिल्ली का नंबर था। अन्य महानगरों और छोटे शहरों में भी यह शोर कम नहीं है। इंसान की बनाई मरीनें, मोटर वाहन, ट्रेनें, हवाई जहाज और निर्माण कार्यों में विस्फोटकों के इस्तेमाल से असहनीय ध्वनियां बातावरण में फैल रही हैं। उन्हें रोकने को लेकर कोई उपाय कारगर साखित नहीं हो रहा है। शोर को समस्या नहीं मानने की एक अहम वजह है कि आम तौर पर लोग ध्वनि प्रदूषण को बायु प्रदूषण की तरह ही सैहत के लिए नुकसानदेह नहीं मानते। उन्हें बायु प्रदूषण के खतरे तो साफ दिखते हैं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण के छिपे खतरों की तरफ उनका ध्यान तक नहीं जाता है। जबकि शोर एक बहुत बड़ा साइलेंट किलर है। सीमा से यादा शोर लोगों को सिर्फ बहरा नहीं बनाता, बल्कि उच रक्तचाप, नींद में खलल और कई अन्य मानसिक विकार भी पैदा कर डालता है। इससे शांत प्रवृत्ति के लोगों का व्यवहार भी हिस्क हो जाता है।

यहां तक कि गर्भस्थ शिशुओं को भी बाहरी शोर काफी यादा नुकसान पहुंचाता है। समयपूर्व प्रसव के लिए कई बार बाहरी शोर ही जिम्मेदार होता है। कहने को तो हमारे देश में पिछले कुछ दशकों में ऐसे प्रदूषण रोकने के लिए कुछ

कायदे-कानून बनाए गए हैं, पर हमारी सरकारें नियम-कानून बनाकर ही अपने कर्तव्य की इतिहासी मान लेती हैं। इसलिए आजादी के बाद इस स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पाया है। वर्ष 2012 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलय के तत्वावधान में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत 25 बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए एक नेटवर्क बनाने की बात कही गई थी। इस नेटवर्क में हर शहर में 10-10 निगरानी केंद्र बनाए गए, जो यह देखते हैं कि कहाँ कितना प्रदूषण है। फिर यदि अभी तक हमारे पास राजधानी दिल्ली को छोड़कर किसी भी शहर के बारे में अधिकृत आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि देश में शोर को मापने की कोई व्यवस्था ठीक ढंग से काम कर ही नहीं रही है।

दिल्ली जैसे शहरों में शोर की मात्र कहीं यादा है, जहां ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करने वाले कई कानून पिछले एक दशक से यादा समय से अस्तित्व में हैं। आवासीय इलाकों में ध्वनि की मात्र अधिकतम 55 डेसिबल, व्यापारिक इलाकों में 65 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्रों में 75 डेसिबल होनी चाहिए, लेकिन हर जगह यह करीब 25 डेसिबल अधिक है। इस कारण कभी-कभी नौबत रोड रेज जैसी घटनाओं की भी आ जाती है। बहरहाल शांति का महत्व जानते हुए भी यह लापरवाही घातक है कि हम शोर को अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने की छूट दे रहे हैं। ध्यान रखना होगा कि सिर्फ कानून ये हालात नहीं बदल सकते। लोगों की मानसिकता बदले बगैर शोर जैसी समस्या से निजात पाना नामुमकिन ही है।

देश के विकास से जुड़े मुद्दों को दलगत राजनीति के चश्म से देखा जा रहा है।

इन दिनों राष्ट्र के विकास और प्रगति से जुड़े मुद्दा को भी दलगत राजनीति के चरमे से देखने का चलन जौर पकड़ रहा है। कोरोना संकट, किसानों की कठिनाइयां, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार या देश की सुक्ष्मा पर जरूरत तो यह है कि सभी पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार-विमर्श करतीं, लेकिन ये विषय भी राजनीतिक पूर्वाग्रह की भेंट चढ़ गए। यह प्रवृत्ति भारत के समग्र उत्थान के लिए खतरनाक है। दलगत राजनीति से अलग सोच रखने वाला सामान्य नागरिक इससे चिंतित है। भला किस देश में सेना द्वारा की गई 'संरिकल स्ट्राइक' का भी प्रमाण मांगा जाता है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि हमारा देश हिंदू-मुस्लिम आधार पर बंटा था। पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों के साथ जो कुछ हुआ, उसे सहकर जो लोग भारत आ सके, उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक कारणों से आज कुछ लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में सतर साल पहले आमंत्रित कर लाए गए दलित समाज के मानवाधिकारों के लिए न तो कभी जुलूस निकाले गए, न ही मोमबत्तियां जलाई गईं।

सीएए का विरोध जिस ढंग से हुआ, वह सत्याग्रह तो कर्तई नहीं था। आज किसान आंदोलन की पटकथा लिखने वाले भी वही हैं जिन्होंने पूर्व में सीएए विरोधी आंदोलन को स्वरूप दिया था। इन्हें याद रखना चाहिए कि विश्व को सत्याग्रह की संकल्पना का पाठ पढ़ने वाले महात्मा गांधी ने चौरी-चौरा की हिंसक घटना के बाद अपने सहयोगियों की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर आंदोलन स्थगित कर दिया था। केवल इसलिए कि सत्याग्रह दुराग्रह में परिवर्तित न हो। हालांकि किसान आंदोलन का सच अब उजागर हो चुका है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे 'किसान' वे नहीं हैं, जो खेतों बगाल म जाकर लगाए किसे नहीं देना है। यहां याद आती है कि चोल मूल प्रवृत्ति छुपाई नहीं रहा है।

स्वार्थ की राजनीति में बेमानी लगती है। देखें सफलता, टीकाकरण अधिक करीब 70 देश विश्व में भारत और भारत समान अर्जित कर रहा रहत् का आधुनिक व्यवहार भारत की प्राचीन संस्कृत से आते-प्रोत है। यदि रहत् का देश में भी आज हर विषय की गैरवाच्चित हो ठोकता, मगर एक पूर्व टीके को भाजपा का टीका इतिहास में अपरिमित उदाहरण जोड़ दिया। यह मिला, जो इस प्रकार बना हो। कोरोना संघर्ष में परिस्क्रिता और दूरविषयी प्रत्येक भारतीय के मन उत्साह की भावना प्रख्यात विश्व भारत की प्रशंसनीय नागरिक अपने विज्ञानियों द्वारा है। यह देश का दुर्भाग्य है ऐसा वर्ग एक जुट नकारात्मकता उजागर देखता है। जब कोई व्यक्ति दल स्वार्थवक्ता राष्ट्र की भी नकराने लगता है, आगे नहीं देख पाता है।

राज्यसभा से भा पास ही गया। लोकसभा ने इस पर 22 मार्च को ही मुहर लगा दी थी। इस बदलाव का मकसद दिल्ली सरकार को पूरी तरह उप-राज्यपाल के अधीन कर देना है। अपने हर फैसले पर दिल्ली सरकार को उनकी राय लेनी पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि यह कानून उनकी सरकार को दबाने के लिए बनाया जा रहा है। यादातर विपक्षी दलों की भी यही राय है। इसीलिए रायसभा में 12 विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया, जबकि नौ ने लोकसभा में इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। विपक्ष का कहना है कि यह कानून देश की संघीय शासन व्यवस्था की नींव पर चोट करता है और असंवैधानिक है।

लेकिन बीजेपी के मुताबिक, इसका मकसद सर्विधान के दायरे के अंदर रहते हुए दिल्ली सरकार और उप-रायपाल की शक्तियों को लेकर भ्रम की गुंजाइश खत्म करना है ताकि राजकाज में कोई दिक्कत न आए। इसके लिए उसने 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें उसने कहा था कि दिल्ली सरकार को रोजमर्रा के काम के लिए उप-रायपाल से सहमति लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि इस फैसले से जो अनिश्चितता और भ्रम बना, उसे खत्म करने के लिए उसकी सरकार को यह कानून बनाना चाहिए।

इसलिए मामला सुप्रीम काट गया। यह भी सच है कि उस फैसले से दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित हुए थे।

लेकिन तब से अबतक दोनों सरकारों के बीच ऐसा कोई मसला नहीं दिखा है, इसलिए पूछा जा रहा है कि केंद्र को अचानक यह कानून क्यों बनाना पड़ा? कुछ लोग इसे दिल्ली के जनादेश का अपहरण भी बता रहे हैं, क्योंकि उससे निकली सरकार की जबाबदेही अब जनता से याद उप-रायपाल के प्रति होगी। केंद्र के इस कानून से दिल्ली को पूर्ण राय का दर्जा देने-दिलाने का मामला अर्थहीन हो गया है। ध्यान रहे, यह बाद दिल्ली की तीनों प्रमुख पार्टियां-आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस हर चुनाव में करती आई हैं। दूसरे, संघीय व्यवस्था पर चोट की जो बात विपक्ष ने कही है, वह भी बेवजह नहीं है।

बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के सत्ता में आने के बाद से यह सवाल अक्सर उठता रहा है। केंद्र और विपक्ष शासित रायों के बीच अधिकारों को लेकर टकराव भी हो रहे हैं। विपक्ष शासित रायों ने केंद्र पर सीबीआई और एनआईए जैसी अपनी एजेंसियों के जरिये उनके कामकाज में अड़ांगा लगाने की बात कही है जबकि केंद्र ने करप्शन मामलों की जांच में एजेंसियों के साथ सहयोग न करने का आरोप

नाम की दिल्ली सरकार

एनसीटी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बिल, 2021 बुधवार 24 मार्च को राज्यसभा से भी पास हो गया। लोकसभा ने इस पर 22 मार्च को ही मुहर लगा दी थी। इस बदलाव का मकसद दिल्ली सरकार को पूरी तरह उप-राज्यपाल के अधीन कर देना है। अपने हार फैसले पर दिल्ली सरकार को उनकी राय लेनी पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि यह कानून उनकी सरकार को दबाने के लिए बनाया जा रहा है। यादातर विपक्षी दलों की भी यही राय है। इसीलिए रायसभा में 12 विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया, जबकि नौ ने लोकसभा में इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। विपक्ष का कहना है कि यह कानून देश की संघीय शासन व्यवस्था की नींव पर चोट करता है और असंवैधानिक है।

लेकिन बीजेपी के मुताबिक, इसका मकसद स्विधान के दायरे के अंदर रहते हुए दिल्ली सरकार और उप-रायपाल की शक्तियों को लेकर भ्रम की गुंजाइश खत्म करना है ताकि राजकाज में कोई दिक्षित न आए। इसके लिए उसने 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें उसने कहा था कि दिल्ली सरकार को रोजरारा के काम के लिए उप-रायपाल से सहमति लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि इस फैसले से जो अनिश्चितता और भ्रम बना, उसे खत्म करने के लिए उसकी सरकार को यह कानून बनाना चाहती है।

और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों को लेकर टकराव चल रहा था, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट गया। यह भी सच है कि उस फैसले से दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित हुए थे।

लेकिन तब से अबतक दोनों सरकारों के बीच ऐसा कोई मसला नहीं दिखा है, इसलिए पूछा जा रहा है कि केंद्र को अचानक यह कानून क्यों बनाया पड़ा? कुछ लोग इसे दिल्ली के जनादेश का अपहण भी बता रहे हैं, क्योंकि उससे निकली सरकार की जवाबदेही अब जनता से यादा उप-रायपाल के प्रति होगी। केंद्र के इस कानून से दिल्ली को पूर्ण राय का दर्जा देने-दिलाने का मामला अर्थहीन हो गया है। ध्यान रहे, यह बाद दिल्ली की तीनों प्रमुख पार्टीयां-आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस हर चुनाव में करती आई हैं। दूसरे, संघीय व्यवस्था पर चोट की जो बात विपक्ष ने कही है, वह भी बेवजह नहीं है।

बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के सत्ता में आने के बाद से यह सवाल अक्सर उठता रहा है। केंद्र और विपक्ष शासित रायों के बीच अधिकारों को लेकर टकराव भी हो रहे हैं। विपक्ष शासित रायों ने केंद्र पर सीधी आई और एनआई और जैसी अपनी एजेंसियों के जरिये उनके कामकाज में अड़ंगा लगाने की बात कही है जबकि केंद्र ने करप्शन मामलों की जांच में एजेंसियों के साथ सहयोग न करने का आरोप

क्वाड के जरिये भारत हिंद महासागर में चालबाज चीन को कर सकता है कमज़ोर

रूस की दृष्टि में भारत का इस समूह में शामिल होना अनैतिक है। दरअसल रूस को लगता है कि आगे चलकर क्वाड उसके लिए भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में खतरा साबित हो सकता है। अमेरिका और रूस एक-दूसरे के विरोधी हैं। चूंकि क्वाड पर नियंत्रण अमेरिका का भी रहेगा और समय के साथ उसका प्रभुत्व बढ़ भी सकता है। ऐसे में भारत यदि रूस के विपरीत खेमे का हिस्सा बनता है तो हिंद प्रशांत में जो रूसी बेड़ा है उसके लिए भी खतरा हो सकता है। हालांकि यहां रूस की शंका वाजिब नहीं है, क्योंकि भारत कभी भी रूस विरोधी गतिविधि में शामिल होने वाली स्तर १में रहता है।

विदेश नीति एक निरंतरशील प्रक्रिया है और प्रगतिशील भी, जहां विभिन्न कारक भिन्न-भिन्न स्थितियों में अलग-अलग प्रकार से देश-दुनिया को प्रभावित करते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर नए-नए मंचों की न केवल खोज होती है, बल्कि व्यापास समस्याओं से निपटने के लिए वैधित्र देशों में एक जुटाता को भी ऊँचाई देनी होती है। क्वाड का इन दिनों वैधिक फलक पर उभरना इस बात को पुख्ता करता है। क्वाड (क्राडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग) भारत समेत जापान, ॲस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक वर्तुष्कोणीय समझौता है। इसका उद्देश्य हिंदू प्रशंसन क्षेत्र में काम करना है, ताकि समुद्री रास्तों पर होने वाले व्यापार को आसान किया जा सके। मगर एक सच यह भी है कि अब यह व्यापार के पाथ-साथ सैनिक बेस को मजबूती देने की ओर भी है। ऐसा इसलिए ताकि शक्ति संतुलन को कायम किया जा सके। हालांकि इन चारों देशों की अपनी प्राथमिकताएं हैं और आपसी सहयोग की सीमाएं भी।

हिमायती रह
भी अछे संब
से अछे संब
उससे कहीं
है। इसके अ
पश्चिम के
अमेरिका के

इ। भारत पाकिस्तान और चीन से चाहता है। वह जितना अमेरिका बनाए रखने का इरादा दिखाता है धेक रूस के साथ नाता जोड़े हुए वा सार्क, आसियान, ओपेक और गों समेत अफीकी तथा लैटिन देशों के साथ उसके रिश्ते कहीं आसियान देश भी दबी ज़ुबान चीन का विरोध करते हैं, पर खुलकर सामन नहीं आ पाते। दक्षिण कोरिया भी दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से काफी खफा रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर का सिलसिला अभी थमा नहीं है। कोरोना वायरस के चलते भी चीन दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर है। जाहिर है कि

जारिये भारत हिंदू महासागर में उसे कमज़ोर कर सकता है। साथ ही हिंदू प्रशांत क्षेत्र में भी अपनी भूमिका बढ़ा सकता है। यहीं चीन की बौखलाहट का प्रभुत्व कारण है। रूस की दृष्टि में भारत का इस समूह में शामिल होना अनौतिक है। दरअसल रूस को लगता है कि आगे चलकर क्राड उसके लिए हिंदू प्रशांत क्षेत्र में खतरा साबित हो सकता है। अमेरिका और रूस एक-दूसरे के विरोधी हैं। चूंकि क्राड पर नियंत्रण अमेरिका का भी रहेगा और समय के साथ उसका प्रभुत्व बढ़ भी सकता है। ऐसे में भारत यदि रूस के लिपरीत खेमे का हिस्सा बनता है तो हिंदू प्रशांत में जो रूसी बेड़ा है उसके लिए भी खतरा हो सकता है। हालांकि यहां रूस की शका वाजिब नहीं है, क्योंकि भारत कभी भी रूस विरोधी गतिविधि में शामिल होने की सोच भी नहीं सकता है। दरअसल क्राड केवल चीन को ध्यान में रखकर बनाया गया एक औपचारिक संगठन है। और शायद भारत इसके अलावा किसी और रूप में क्राड को देखता भी नहीं है, पर शंका समाप्त करने के लिए इस मामले में भारत को रूस से खुलकर बात करनी चाहिए।

एक नजर

नंदीग्राम का महासंग्राम : सुवेंदु का बड़ा हमला, कहा-‘बेगम’ ममता बनर्जी बंगाल को बना देंगी ‘मिनी पाकिस्तान’

कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में वारपलटवार का दौर जारी है। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बार पर भाजा प्राप्त नेता और नंदीग्राम सीट से तुम्हारू कांग्रेस सुप्रीमों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे सुवेंदु अधिकारी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और उनपर मुख्यमंत्री का तुषीकण करने का आरोप लगाया।

नंदीग्राम में चुनावी सुवेंदु ने कहा, ‘ममता बनर्जी को ‘इंदुमुकाब’ कहने की आदत है। इसीलिए उन्होंने आज हाली की बढ़ियाँ की जगह आप सभी को ‘होली मुकाब’ कहा। बेगम को बोट मत दीजिए। आप आप बेगम को बोट देंगे तो यह (बंगाल) मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। बेगम, सुकियान के अलावा किसी को नहीं जानती। बेगम अचानक बदल गई। और मर्दों में जानवीर सुवेंदु ने कहा, ‘ममता बनर्जी को ‘इंदुमुकाब’ कहने की आदत है। इसीलिए उन्होंने आज हाली की बढ़ियाँ की जगह आप सभी को ‘होली मुकाब’ कहा।

सुवेंदु ने अपने कहा कि आज लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के बाद उड़ जाएंगे, जबकि वह (अधिकारी) यहाँ के स्थाई निवासी हैं और लोगों के सुख-दुख के लिए दिन-रात भौजूद रहेंगे। अंडियों लोक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) का जो अंडियों सामने आया है उसमें सुधा जा सकता है। आपने भी नहीं आया था। और अगे भी नहीं आया था। ऐसे में वह लगातार झटक बोलती है कि नंदीग्राम के लोगों के लिए हमेशा रही है। सच्चाई यही है कि नंदीग्राम में वह कभी नहीं थी।

बता दें कि आज ही ममता ने नंदीग्राम की सभा में सुवेंदु अधिकारी पर यूपी-बिहार के गुडों से मदर मामले का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि वह रोल बंगाल टाइम है और मूल बाप से धाया बाप ज्यादा खरानक होता है। सोमवार के बाद उड़ जाएंगे, पर बैठकर आठ किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके जबाब में सुवेंदु अधिकारी ने पांच जनसभाओं को संबोधित किया है और ममता बनर्जी को बाहरी करार दिया।

कोयला तस्करी मामले में चार महीने से फरार किंगपिन लाला कोलकाता में सीबीआई के समक्ष हुए हाजिर

कोलकाता। हजारों कोरड़ रुपए के कोयला तस्करी मामले में चार महीने से फरार किंगपिन अनुप माजी उर्फ लाला मंगलवार को कोलकाता में सीबीआई के समस्त हाजिर होनी आई। एटी करशन बांध को मंगलवार को लाला को हाजिर होने के लिए काढ़ा करा था। सिफ महबूबा मुफ्ती ही नहीं उनकी मां लालशन मुफ्ती को भी जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीबीआई विंग को नकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रीय विंगरों द्वारा दिए गए थे। लाला से पृथक्तात्री की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताते चलें कि सीबीआई ने लाला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। इसके साथ ही उनकी संपत्ति जबत करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

महबूबा को पासपोर्ट के लिए उच्च न्यायालय से भी नहीं मिली मदद, कहा-यह मेरे कार्याधिकार में नहीं

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अपने पासपोर्ट के लिए उच्च न्यायालय से भी कोई मदद नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने इसे अपने कार्याधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताते हुए इसमें दखल देने से इकार कर दिया था। सिफ महबूबा मुफ्ती ही नहीं उनकी मां लालशन मुफ्ती को भी किंम्बु-कश्मीर पुलिस के सीबीआई विंग को नकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रीय विंगरों द्वारा दिए गए थे। सीबीआई ने पीडीपी अध्यक्षा की विवेश यात्रा को राष्ट्रीय एकता व सुक्षमा के लिए देखे थे। दोनों पासपोर्ट देने से इकार कर दिया है। सीबीआई ने एक पीडीपी अध्यक्षा की विवेश यात्रा को राष्ट्रीय एकता व सुक्षमा के लिए देखे थे। दोनों पासपोर्ट देने से इकार कर दिया है।

खतरा बताया है। उल्लेखनीय है कि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में देशी को देखते हुए महबूबा मुफ्ती ने जीते सपात जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय में जस्टिस अली मोहम्मद मामरे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अली मोहम्मद मामरे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मेरी राय वह अदालत याचिकाकर्ता के पास में पासपोर्ट जारी करने की कोई शर्त नहीं है। एक रिपोर्ट जारी करने की कोई शर्त नहीं है। उच्च अदालत के याचिकाकर्ता के पास कोई शर्त नहीं है। अदालत सिर्फ संविधान संस्था को संबोधित नियमों के आधार पर आवेदक को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ही कह सकती है। इसके पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्रीनगर ने उच्च न्यायालय में एडीजीपी सीबीआई जम्मू-कश्मीर के एक रिपोर्ट भी जमा करते हुए देखा कि सिफारिश से इकार किया है। नियमों के मुताबिक पुलिस की जांच रिपोर्ट पासपोर्ट के लिए अनिवार्य है। सीबीआई को एक रिपोर्ट के आधार पर महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट आवादन पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने 11 दिसंबर 2020 को पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया था। महबूबा मुफ्ती को भी नहीं उद्दीप्त किया जाता है। एक रिपोर्ट देने से इकार कर दिया है। सीबीआई ने एक पीडीपी अध्यक्षा की विवेश यात्रा को राष्ट्रीय एकता व सुक्षमा के लिए देखे थे। दोनों पासपोर्ट देने से इकार कर दिया है। सीबीआई ने एक पीडीपी अध्यक्षा की विवेश यात्रा को राष्ट्रीय एकता व सुक्षमा के लिए देखे थे। दोनों पासपोर्ट देने से इकार कर दिया है।

खतरा बताया है। उल्लेखनीय है कि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में देशी को देखते हुए महबूबा मुफ्ती ने जीते सपात जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय में जस्टिस अली मोहम्मद मामरे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अली मोहम्मद मामरे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मेरी राय वह अदालत याचिकाकर्ता के पास में पासपोर्ट जारी करने के मामलों में इस अदालत के पास कोई ज्यादा अधिकार नहीं है। अदालत सिर्फ संविधान संस्था को संबोधित नियमों के आधार पर आवेदक को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ही कह सकती है। इसके पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्रीनगर ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय में जस्टिस अली मोहम्मद मामरे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अली मोहम्मद मामरे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मेरी राय वह अदालत याचिकाकर्ता के पास में पासपोर्ट जारी करने के मामलों में इस अदालत के पास कोई ज्यादा अधिकार नहीं है। अदालत सिर्फ संविधान संस्था को संबोधित नियमों के आधार पर आवेदक को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ही कह सकती है। इसके पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्रीनगर ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय में जस्टिस अली मोहम्मद मामरे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अली मोहम्मद मामरे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मेरी राय वह अदालत याचिकाकर्ता के पास में पासपोर्ट जारी करने के मामलों में इस अदालत के पास कोई ज्यादा अधिकार नहीं है। अदालत सिर्फ संविधान संस्था को संबोधित नियमों के आधार पर आवेदक को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ही कह सकती है। इसके पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्रीनगर ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय में जस्टिस अली मोहम्मद मामरे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अली मोहम्मद मामरे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मेरी राय वह अदालत याचिकाकर्ता के पास में पासपोर्ट जारी करने के मामलों में इस अदालत के पास कोई ज्यादा अधिकार नहीं है। अदालत सिर्फ संविधान संस्था को संबोधित नियमों के आधार पर आवेदक को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ही कह सकती है। इसके पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्रीनगर ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय में जस्टिस अली मोहम्मद मामरे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अली मोहम्मद मामरे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मेरी राय वह अदालत याचिकाकर्ता के पास में पासपोर्ट जारी करने के मामलों में इस अदालत के पास कोई ज्यादा अधिकार नहीं है। अदालत सिर्फ संविधान संस्था को संबोधित नियमों के आधार पर आवेदक को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ही कह सकती है। इसके पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्रीनगर ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय में जस्टिस अली मोहम्मद मामरे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अली मोहम्मद मामरे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मेरी राय वह अदालत याचिकाकर्ता के पास में पासपोर्ट जारी करने के मामलों में इस अदालत के पास कोई ज्यादा अधिकार नहीं है। अदालत सिर्फ संविधान संस्था को संबोधित नियमों के आधार पर आवेदक को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ही कह सकती है। इसके पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्रीनगर ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय में जस्टिस अली मोहम्मद मामरे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अली मोहम्मद मामरे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मेरी राय वह अदालत याचिकाकर्ता के पास में पासपोर्ट जारी करने के मामलों में इस अदालत के पास कोई ज्यादा अधिकार नहीं है। अदालत सिर्फ संविधान संस्था को संबोधित नियमो

फातिमा सना शेर्य

हुई कोरोना पॉजिटिव, सोशल
मीडिया पर किया ये पोस्ट



फातिमा ने बताया कि उन्होंने खुद को घर में अलग-थलग कर लिया है और लोगों से प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है।

अभिनेत्री फातिमा सना शेर्य ने कोविड-19 की जांच करवाई, जिसमें वह कोरोनावायरस से संक्रमित पाई गई हैं। सोमवार को पोस्ट किए एक संदेश में फातिमा ने बताया कि उन्होंने खुद को घर में अलग-थलग कर लिया है और लोगों से प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, **‘क्षम’ कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव निकली। इस समय सभी सावधानियों और प्रोटोकॉल का पालन कर रही हूं। आप सबकी शुभेच्छाओं और चिंता के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें दोस्तों।’**

फिल्म दंगल में फातिमा के पिता की भूमिका निभा चुके अभिनेता आमिर खान भी कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, विकांत मैसी, परेश रावल, मिलिंग सोमन, आर. माधवन और रोहित सराफ सहित कई बॉलीवुड हस्तियां करोना की चपेट में आ चुके हैं। फिल्म तहान में भी अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को 2009 में जर्मनी में हुए बॉलीवुड एंड बियोंड फेस्टीवल में द जर्मन स्टार ऑफ इंडिया अवार्ड मिला ? था।

इतना ही नहीं फातिमा ने फिल्मों के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी काम किया है। लेडीज स्पेशल, बेस्ट ऑफ लक निक्की और अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीओजों में काम कर चुकी हैं। फातिमा ने करियर की ये बुलदियां अपने दम और कड़ी स्ट्यूल के जरिए हासिल की हैं। फिल्मों में फातिमा का कभी कोई गोड़फादर नहीं रहा है। दंगल इतनी सुपरहिट फिल्म थी कि उसके बाद एक्ट्रेस फातिमा से काफी उम्मीदें बढ़ गईं। उसके बाद उन्होंने फिल्म टग्स ऑफ हिंदुस्तान, लूडो और सूरज पे मंगल भार में काम किया हैं। लूडो और सूरज पे मंगल भारी ओटीटी ? पर रिलीज हुई लेकिन यह फिल्म दंगल जैसा कमाल नहीं कर पाई इसलिए आज भी ज्यादातर लोग दंगल गर्ल के नाम से ही फातिमा सना शेर्य को पहचानते हैं। उनकी आने वाली फिल्म भूत पुलिस जिसमें अभिनेता सेफ अली खान और अली फजल के साथ नजर आएंगी।



करीना कपूर सारा अली खान

ने की पूल पार्टी, व्हाइट बिकिनी पहनें तरवीरे वायरल

बीते दिन पूरे देश में होली की धूम देखने को मिली, ऐसे में बॉलीवुड के सितारों ने भी खुब मस्ती की। इस बीच बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैन्स को भी बधाई दी। इस बीच सारा अली खान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं, जिनमें वो व्हाइट

बिकिनी में नजर आ रही हैं।

सारा का देसी अंदाज

दरअसल होली के बाद सारा

अली खान, पिता सैफ अली

खान और करीना कपूर खान के

नए घर पहुंचे। इस खास मौके पर

सारा बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

सफेद सूट के साथ रंग बिरंगी चुड़ियों

में सारा अली खान ने सभी का दिल जीत

लिया। सारा के ये फोटोज फैन्स की

खूब पसंद आए।

बिकिनी में फोटोज हुए वायरल

ई-टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीना और

सैफ के घर होली के खास मौके पर पूल पार्टी रखी

गई, जहां से सारा अली खान का कुछ बेहद बोल्ड

प्रियंका चोपड़ा ने ससुराल में
सेलिब्रेट की होली, पति निक जोनस
और सास-ससुर पर भी चढ़ा रंग



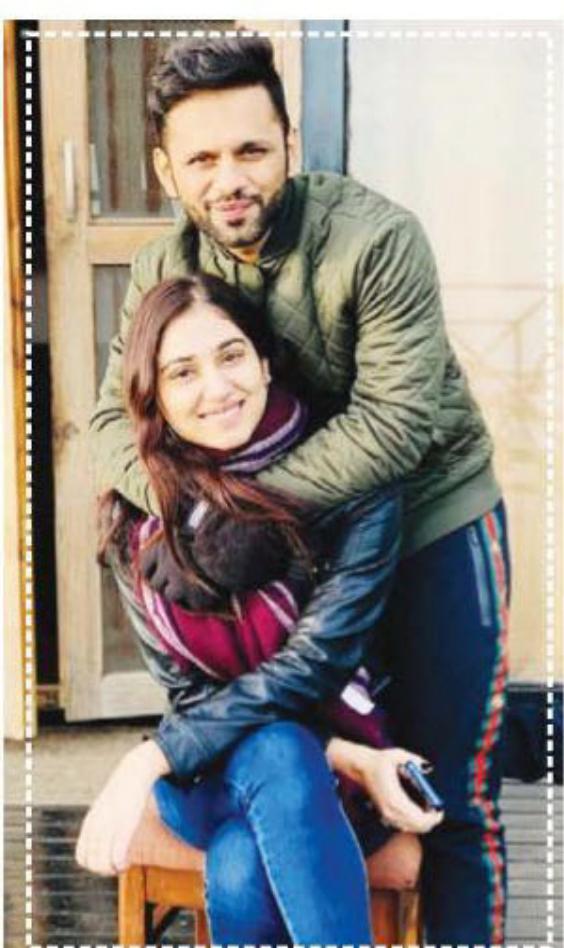
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भले ही अपने पति जोनस के साथ विदेश में सेटर हो गई हैं, लेकिन वहां रहकर भी वो भारत की परंपराओं और त्यागों को नहीं भूलती हैं। चाहे होली हो, दीवाली हो या करवाचौथ... एक्ट्रेस विदेश में रहकर भी अपने साथ त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं और अपने फैंस को बधाई देना नहीं भूलती हैं। आज होली के मौके पर प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं जिनमें वो पति निक जोनस और सास-ससुर के साथ होली के रंग में रंगी नजर आ रही हैं।

एक्ट्रेस की फोटो में दिख रहा है कि प्रियंका सेमर सभी ने सफद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और सभी लोगों के कपड़ों और चांदर पर लाल पीले रंग लगे हुए हैं। फोटो में प्रियंका ने हाथ में पिचकारी पकड़ी हुई है तो वहीं सभी कैमरे की तरफ देखकर फोज़ दे रहे हैं। इस फोटो के अलावा एक्ट्रेस कुछ और भी फोटोज़ शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा है, ‘होली संगों का त्यौहार मेरे फैंसरों लोगों के साथ... हम सब इस्टा पर लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अपने घर पर’। आप भी देखें फोटोज़। आप भी देखें फोटोज़।

प्रियंका को पति और अमेरिकन पॉप स्टार निक जोनस ने भी यही फोटोज़ अपने इंस्टा पर शेयर करते हुए सभी को होली की बधाई दी है।

प्रियंका के अलावा तमाम अधिकारी बच्चन, सारा अली खान, करीना कपूर खान, अर्जुन रामपाल, कंगना रनोट, रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूज समेत कई बॉलीवुड सितारों ने होली के मौके पर अपने फैंस को देंडर सारी शुभकामनाएं दी हैं। बिसी ने अपने परिवार के साथ थ्रोबैक फोटो शेयर की है तो किसी ने फनी बीड़ियों शेयर कर लोगों को होली की बधाई दी है।

**Holi पर एक दूसरे के प्यार में झूमे
दिखे राहुल वैद्य और दिशा परमार,
शेयर कीं ये रोमांटिक फोटोज़**



आज पूरा देश रंगों के त्यौहार होली के रंग में झूमा हुआ है तो ऐसे में सेलिब्रेट कैसे पीछे हट सकते हैं। हालांकि कोरोना के खतरे ने इस बार होली का रंग थोड़ा फोका कर दिया है, लेकिन लोग फिर भी अपने खास लोगों के साथ थोड़ा बहुत होली सेलिब्रेशन तो कर ही रहे हैं। फैमस सिंगर और बिंग बॉस 14 फाइलिस्ट राहुल वैद्य ने अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार के साथ होली सेलिब्रेट की है। राहुल और दिशा के होली सेलिब्रेशन की फोटोज़ शेयर की हैं जिनमें दोनों रंगों के साथ खेलते दिख रहे हैं। इन रोमांटिक फोटोज़ में राहुल और दिशा एक दूसरे के घर में झूमे दिख रहे हैं कि राहुल ने दिशा को बड़े सुकून के साथ गले लगा रखा है और दिशा भी घर से उड़े थामे हुए दिख रही है। दोनों की ये रोमांटिक फोटोज़ फैंस को भी काफी पसंद आ रही हैं। फोटोज़ शेयर करते हुए राहुल ने सभी को होली की मुवारकबाद दी है। इन फोटोज़ के अलावा राहुल ने दिशा के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें सिंगर अपनी गर्लफ्रेंड को रंग लगाने के लिए भागते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो और फोटोज़ में दोनों सफेद रंग का बहुत अधिक जॉस पहुंच हुई है और दोनों बड़ी मस्ती के साथ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं।

आपको बताते हुए राहुल और दिशा फिलहाल सोशल मीडिया के सबसे फैमस और फैवरेट कपल में से एक हैं। राहुल ने दिशा को बिंग बॉस 14 के दीवान प्यारी किया था उसके बाद से ही दोनों जहां भी साथ में जाते हैं वहां पैपराज़ी उनके पांछे पहुंच जाते हैं। दोनों की फोटोज़ सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती हैं।

इयान बेल ने बताया, किस प्लेयर के बिना अब टीम इंडिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती

नई दिल्ली। रिखभ पंत को भारत के ऑस्ट्रेलिया दैरे पर जैसे ही दूसरे टेस्ट मैच में प्लेइंग इलेवन में मौका मिला, उन्होंने पीछे मुड़न नहीं देखा और अनेक प्रश्न के दम पूर्व वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट, टी20 और वनडे सीरीज का भी हिस्सा बने। इंग्लैंड के खिलाफ तीनों प्रारूपों की सीरीज में रिखभ का बल्लं जमकर चला और वो भारतीय टीम के तरफ से खिलाफ के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी भी रहे। बल्के के बाद-साथ विकेट के पीछे भी उन्होंने कामाल दिखाया और अच्छा प्रश्न किया।

रिखभ पंत ने पहले टेस्ट सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी अच्छा खेल दिखाया और फिर वनडे सीरीज में दो मैचों में बैक-टू-बैक अंशशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड के खिलाफ तीनों प्रारूपों की सीरीज के मैच प्रदर्शन करने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टीमी इयान बेल ने उनकी खेल तारीफ की। बेल ने इंग्लैंड के खिलाफ टीमी इयान बेल के बारे में कहा कि, उनके लिए ये क्रिकेट सीरीज काफी अच्छी रही।

बेल ने कहा कि, इंग्लैंड के खिलाफ रिखभ पंत ने सभी प्रारूपों में बिना किसी हड्डीडाट के बल्लेबाजी की। वो बिल्कुल शांत नजर आए और कैपी ऐसा नहीं लगा कि, वो रिखभ ले रहे हैं। वो लगातार स्ट्राइक रोटेशन करते रहे और मैं कल्पना करता हूं कि उनके सामने गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज जस्तर ये सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने गलती की तो उसका खिमियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैंने इस सीरीज के दौरान देखा कि, किस तरह से उनकी परिषक्ता और ज्ञान बढ़ गई थी। इसके अलावा टेस्ट मैच में उन्होंने जो शतक लगाया था उससे उनका आत्मविश्वास और ज्ञान बढ़ा।

भारतीय दिग्गज ने बताया, इस तरह वनडे क्रिकेट में शतक ठोक सकते हैं हार्दिक पांड्या

नई दिल्ली। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पुणे में खिलाफ को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में 44 गेंदों पर 64 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसकी बदौलत भारत ने 300 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया और फिर भारत ने क्रीड़ा मुकाबले में 7 स्नों से जीत दर्ज कर सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। हार्दिक पांड्या और रिखभ पंत के बाद 5वें विकेट के लिए अच्छी साझेदारी हुई।

27 वर्षीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने हाल के दिनों में बल्ले से लगातार योगदान दिया है, लेकिन वे कई बार शतक के करीब पहुंचकर भी शतक नहीं बना सकते हैं। वनडे क्रिकेट में उनके नाम 7 अंशशतक की तरफ तक शतक नहीं बना पाए हैं। इस पर पवर भारतीय क्रिकेट से कमटेश्वर बने अकाश चोपड़ा ने राय दी है कि अगर पांड्या को बल्लेबाजी क्रम में पदान्त्रित किया जाता है तो पांड्या वनडे में शतक जड़ सकते हैं। स्टार्टस स्ट्रोर्ट्स नेटवर्क पर बोलते हुए अकाश चोपड़ा ने कहा, “हार्दिक पांड्या इमानदारी से मैं लिए अब एक चैम्पियन बल्लेबाज करते हैं तो वह पांस शतक बनाया। यदि अप उनसे उपर के क्रम में बल्लेबाजी करते हैं तो दस में से जो बार अप क्रिकेटिंग शॉटस देखते हैं, तो दस में से जो बार उनकी उम्हें अच्छी तैयारी की है।”

अकाश चोपड़ा ने अगर कहा, एक समय में जब अधिकारी वनडे मैच में भारत के चार विकेट गिर चुके थे। जब केएल राहुल आउट हुए, तो लाल कि पारी खेली गई है। इसके बाद उन्होंने (हार्दिक पांड्या) जिस तरह की बल्लेबाजी की, उन्हें ताकत है। उन्होंने अपने बल्लेबाजी सॉफ्टवेयर को जल्दी अपडेट किया और फिर एक प्रोप्र बल्लेबाज की तरह खेलना शुरू कर दिया है। वह क्रीज की गहराई का अच्छे से इत्तेमाल कर सकते हैं।

मोहम्मद शमी ने किया दावा, कहा - पंजाब किंग्स को अब इस विभाग में कोई दिवकत नहीं है

नई दिल्ली। पिछले साल संयुक्त अब अमीरत यानी याई में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए थ्रेट गेंदबाजी चिंता का कारण रही थी, क्योंकि शेल्डन कॉटेल जैसे गेंदबाजों को एक-एक ओवर में 4-4 छक्के पड़े थे। अब अकाश महसूस करते हैं कि अपने गेंदबाजी की तरफ तक फिटेस में समस्या नहीं देखी थी, लेकिन यह एक अच्छी चीज थी जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन यह एक ऐसी चीज थी कि इसका बिल्कुल ठीक है और खेलने के लिए तैयार है। बल्लेबाजी करते समय चोट लगना दुष्प्रयोगी था, क्योंकि मैं लंबे समय तक फिटेस में समस्या नहीं देखी थी, लेकिन यह एक ऐसी चीज थी कि इसका बिल्कुल ठीक है और खेलने के लिए अच्छी करियर का सामना असम्भव था। यह उन्होंने 8.57 की गेंदबाजी से 20 विकेट लिए थे, लेकिन उन्हें अच्छी गेंदबाजी की ओर खिलाफ से ज्यादा समर्थन नहीं मिला, जो थ्रेट ओवरों में से जो नहीं बचा पाते थे, अंततः टीम को इसकी मार जेलनी पड़ी, क्योंकि टीम प्लेआफ की बर्थ हासिल नहीं कर पाई थी। हालांकि, अब टीम ने ज्यादा रिचर्ड्सन, रिली मेरिडिंग और मैडिसन डेवेनिस को इस अंतर को पूरा करने के लिए साथ जोड़ा है तो गेंदबाज शमी न कहा, हम अंतीम को नहीं बदल सकते हैं। मैंने पिछले सीजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और जब भी मैं साथी तेज गेंदबाजों की मदद कर सकता था, मैंने की।

ऋषभ पंत पर ‘आकाशवाणी’: पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने पंत की तुलना डिविलियर्स और गिलक्रिस्ट से की, कहा-

रिस्क लेना ही ऋषभ की सबसे बड़ी ताकत

पूछे। टीम इंडिया ने हाल ही में इंग्लैंड को बनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी। इसमें ऋषभ पंत को दो मैच में मौका मिला था, जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ किसी लगाई। अपनी दोनों पारियों से उन्होंने फेस समेत सभी दिग्नायों को कालाकर किया। इसी बांध पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने पंत को स्पेशल मैचों की तरफ खिलाफ तीमी इयान बेल के बाद इंग्लैंड की टीमी इयान बेल ने उनकी खेल तारीफ की। बेल ने इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत को साथ-साथ सीरीज में उनकी खेल तारीफ की। बेल ने कहा कि, उनके लिए ये क्रिकेट सीरीज काफी अच्छी रही।

चोपड़ा ने पंत की खेलने के बाद-साथ खिलाफ तीमी इयान बेल के बाद उन्होंने कामाल दिखाया और अच्छा प्रश्न किया।

रिखभ पंत ने पहले टेस्ट सीरीज में अच्छे प्रदर्शन करने के बाद इंग्लैंड की टीमी इयान बेल के बाद उनकी खेल तारीफ की। बेल ने इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत को साथ-साथ सीरीज में उनकी खेल तारीफ की। बेल ने कहा कि, उनके लिए ये क्रिकेट सीरीज काफी अच्छी रही।

चोपड़ा ने पंत की खेलने के बाद-साथ खिलाफ तीमी इयान बेल के बाद उन्होंने कामाल दिखाया और अच्छा प्रश्न किया।

रिखभ पंत ने पहले टेस्ट सीरीज में अच्छे प्रदर्शन करने के बाद इंग्लैंड की टीमी इयान बेल के बाद उनकी खेल तारीफ की। बेल ने इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत को साथ-साथ सीरीज में उनकी खेल तारीफ की। बेल ने कहा कि, उनके लिए ये क्रिकेट सीरीज काफी अच्छी रही।

चोपड़ा ने पंत की खेलने के बाद-साथ खिलाफ तीमी इयान बेल के बाद उन्होंने कामाल दिखाया और अच्छा प्रश्न किया।

रिखभ पंत ने पहले टेस्ट सीरीज में अच्छे प्रदर्शन करने के बाद इंग्लैंड की टीमी इयान बेल के बाद उनकी खेल तारीफ की। बेल ने इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत को साथ-साथ सीरीज में उनकी खेल तारीफ की। बेल ने कहा कि, उनके लिए ये क्रिकेट सीरीज काफी अच्छी रही।

चोपड़ा ने पंत की खेलने के बाद-साथ खिलाफ तीमी इयान बेल के बाद उन्होंने कामाल दिखाया और अच्छा प्रश्न किया।

रिखभ पंत ने पहले टेस्ट सीरीज में अच्छे प्रदर्शन करने के बाद इंग्लैंड की टीमी इयान बेल के बाद उनकी खेल तारीफ की। बेल ने इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत को साथ-साथ सीरीज में उनकी खेल तारीफ की। बेल ने कहा कि, उनके लिए ये क्रिकेट सीरीज काफी अच्छी रही।

चोपड़ा ने पंत की खेलने के बाद-साथ खिलाफ तीमी इयान बेल के बाद उन्होंने कामाल दिखाया और अच्छा प्रश्न किया।

रिखभ पंत ने पहले टेस्ट सीरीज में अच्छे प्रदर्शन करने के बाद इंग्लैंड की टीमी इयान बेल के बाद उनकी खेल तारीफ की। बेल ने इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत को साथ-साथ सीरीज में उनकी खेल तारीफ की। बेल ने कहा कि, उनके लिए ये क्रिकेट सीरीज काफी अच्छी रही।

चोपड़ा ने पंत की खेलने के बाद-साथ खिलाफ तीमी इयान बेल के बाद उन्होंने कामाल दिखाया और अच्छा प्रश्न किया।

रिखभ पंत ने पहले टेस्ट सीरीज में अच्छे प्रदर्शन करने के बाद इंग्लैंड की टीमी इयान बेल के बाद उनकी खेल तारीफ की। बेल ने इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत को साथ-साथ सीरीज में उनकी खेल तारीफ की। बेल ने कहा कि, उनके लिए ये क्रिकेट सीरीज काफी अच्छी रही।

चोपड़ा ने पंत की खेलने के बाद-साथ खिलाफ तीमी इयान बेल के बाद उन्होंने कामाल दिखाया और अच्छा प्रश्न किया।

रिखभ पंत ने पहले टेस्ट सीरीज में अच्छे प्रदर्शन करने के बाद इंग्लैंड की टीमी इयान बेल के बाद उनकी खेल तारीफ की। बेल ने इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत को साथ-साथ सीरीज में उनकी खेल तारीफ की। बेल ने कहा कि, उनके ल